राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर – 19,
नया रायपुर (छ.ग.) 492002
ई-मेल : seiaacg@gmail.com

क. 834 / एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. / एसआईए / सीजी / आईएनडी / 468 नया रायपुर, दिनांक 19/01 / 2018

प्रति,

मेसर्स आर.आर.इस्पात
(ए यूनिट ऑफ गोदावरी पावर एण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड),
490 / 1, उरला इण्डस्ट्रीयल काम्प्लेक्स,
ग्राम–उरला,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्लॉट नं 490 / 1, 237 / 3, 237 / 6, 476 / 1, 476 / 2, 483, 484, 485, 486, 490 / 2, 487, 488, 489 / 2, 474, 489 / 1, 488, 474, 489 / 1, 497, 496, 239 / 1, 239 / 2, 240, 241, 236 / 1, 236 / 2, 327 / 1, 327 / 2, 327 / 3, 328 / 1, 328 / 2, 330 / 1, 330 / 2, 324 / 1, 271 / 5 एवं 271 / 6, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर में कुल भूमि 7.899 हेक्टेयर में रोलिंग मिल 1,00,000 टन / वर्ष से 2,14,000 टन / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :– आपका ऑनलाईन आवेदन प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 10815 / 2016 दिनांक 15 / 05 / 2017 एवं अनुवर्ती पत्राचार प्राप्ति दिनांक 15 / 11 / 2017.

——:: 00 ::——

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया आपके संदर्भित पत्र दिनांक 15 / 05 / 2017, 16 / 05 / 2017, 24 / 05 / 2017, 27 / 05 / 2017, 19 / 07 / 2015, 25 / 09 / 2017 एवं 15 / 11 / 2017 का अवलोकन हो।

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 10815 / 2016, यह आवेदन दिनांक 15 / 05 / 2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल 1,00,000 टन / वर्ष से 2,14,000 टन / वर्ष हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था, जो कि प्लॉट नं 490 / 1, 237 / 3, 237 / 6, 476 / 1, 476 / 2, 483, 484, 485, 486, 490 / 2, 487, 488, 489 / 2, 474, 489 / 1, 488, 474, 489 / 1, 497, 496, 239 / 1, 239 / 2, 240, 241, 236 / 1, 236 / 2, 327 / 1, 327 / 2, 327 / 3, 328 / 1, 328 / 2, 330 / 1, 330 / 2, 324 / 1, 271 / 5 एवं 271 / 6, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर में कुल भूमि 7.899 हेक्टेयर के अन्तर्गत क्षमता विस्तार कुल 0.831 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित किया गया था।

- एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1071 दिनांक 26/11/2016 के द्वारा उद्योग को बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु ईआईए रिपोर्ट बनाने बाबत् जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/02/2017 को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

- उपरोक्त प्रकरण पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-11013/36/2014-IA-I दिनांक 04/04/2016 के अनुसार पूर्व में जारी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) में संशोधन कर लोक सुनवाई कराने हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) में संशोधन पत्र क्रमांक 138, दिनांक 29/04/2017 को जारी किया गया।

- लोक सुनवाई दिनांक 09/05/2017 को प्रातः 11:00 बजे स्थान एसटीडीसी भवन औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 12/05/2017 द्वारा प्रेषित किया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई की जानकारी/दस्तावेजों एवं फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15/05/2017 को प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण पर एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 226वीं, 230वीं, 232वीं, 236वीं एवं 241वीं बैठक क्रमशः दिनांक 16/05/2017, 16/06/2017, 26/07/2017, 09/09/2017 एवं 25/11/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए दिनांक 16/05/2017 को श्री दिनेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं दिनांक 26/07/2017 को श्री टी. बोस, उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–उरला 1.0 कि.मी. एवं रायपुर शहर 8.0 कि.मी. की दूरी पर है। समीपस्थ रेल्वे स्टेशन रायपुर 10 कि.मी. तथा रायपुर एयरपोर्ट 20 कि.मी. की दूरी पर है। खारून नदी 5.5 कि.मी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी 3.5 कि.मी. है। प्रोजेक्ट की संचालित इकाई की लागत रूपये 38.49 करोड़ है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर के पत्र दिनांक 07/07/2017 के द्वारा पूर्व प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन के संबंध में टीप प्रेषित गई है। जिसके अनुसार दिनांक 06/01/2011 को प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्रमांक 11 अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संचालन सुनिश्चित करने हेतु पृथक विद्युत मीटर की स्थापना नहीं की गई है। साथ ही शर्त क्रमांक 02, 15, 18, 23 एवं 25 का आंशिक पालन करना बताया गया।
4. **रॉ–मटेरियल** – रोलिंग मिल में रॉ मटेरियल के रूप में माईल्ड स्टील बिलेट्स, स्लेब्स या ब्लूम्स 2,27,465 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा, जो जीपीआईएल द्वारा घरेलु उत्पादन

एवं लोकल मार्केट से प्राप्त किया जावेगा। कोल गैसीफिकेशन सिस्टम हेतु 16,648 टन/वर्ष कोयले की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति एस.ई.सी.एल एवं ओपन मार्केट से की जावेगी।

5. क्षमता विस्तार के तहत् कार्य प्रणाली 02 शिफ्ट (16 घंटे) से बढ़ाकर 03 शिफ्ट (21 घंटे) किया जायेगा। कार्य दिवस 330 से बढ़ाकर 340 दिवस किया जावेगा। स्थापित फर्नेस की उत्पादन क्षमता 30 टन/घंटा है, परंतु वर्तमान में 18 टन/घंटा की उत्पादन क्षमता से कार्यरत है। अतः क्षमता विस्तार पश्चात् फर्नेस की उत्पादन क्षमता 30 टन/घंटा किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार पश्चात् फर्नेस ऑयल का उपयोग नहीं करते हुए कोल गैसीफिकेशन सिस्टम का उपयोग किया जावेगा। प्रति टन बिलेट गर्म करने हेतु 80 किलो कोयले से बनी गैस का उपयोग किया जावेगा।

6. **जल खपत एवं स्त्रोत** – स्थापित रोलिंग मिल हेतु 20 कि.ली./दिन जल की आवश्यकता है। आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड/ सी.एस.आई.डी.सी लिमिटेड से की जाती है। रोलिंग मिल की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता हेतु 30 कि.ली./दिन जल की आवश्यकता होगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ इस्पात भूमि लिमिटेड/ सी.एस.आई.डी.सी लिमिटेड से 50 कि.ली./दिन बाबत् अनुमति ली गई है।

7. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – स्थापित रोलिंग मिल से उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 02 कि.ली./दिन है। रोलिंग मिल की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता से उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 03 कि.ली./दिन होगी। इस प्रकार कुल उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 05 कि.ली./दिन होगी। जिसका उपचार सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट द्वारा किया जावेगा। औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में तथा क्षमता विस्तार के तहत् वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु री–हिटिंग फर्नेस की चिमनी में वेट स्क्रबर लगाया गया है। वर्तमान में स्थापित चिमनी की ऊंचाई 44 मीटर है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाती है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि करना प्रस्तावित नहीं है।

9. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** – स्थापित रोलिंग मिल ईकाई से ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न मिल स्केल की मात्रा 2,080 टन/वर्ष, क्लिंकर ऐश 3,600 टन/वर्ष एवं टार अधिकतम 368 कि.ग्रा./माह है एवं क्षमता विस्तार उपरांत मिल स्केल 4,365 टन/वर्ष, क्लिंकर ऐश 6,848 टन/वर्ष एवं टार अधिकतम 736 कि.ग्रा./माह उत्पन्न होना प्रस्तावित है। मिल स्केल को अपनी फेरो/एसएमएस कुल इकाईयों में पुर्नउपयोग, क्लिंकर ऐश को ब्रिक निर्माण ईकाईयों को एवं टार को अधिकृत क्रेताओं को विक्रय किया जाएगा।

10. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु 12 नग रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया है।

11. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 03 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 04 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

12. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 17.8 से 51.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 23.4 से 82.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 10.1 से 25.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 10.4 से 33.0 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर 38.4 डीबीए से 54.9 डीबीए पाया गया। पूर्व में मॉनिटरिंग किये गये स्थलों पर परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की एक माह (03/10/2017 से 30/10/2017) की अवधि का गुणवत्ता मापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

13. यह क्षेत्र सिवियरली पॉलुटेड एरिया के अंतर्गत आता है। ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने के दौरान किये गये मॉनिटरिंग के अनुसार परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की मात्रा इस क्षेत्र हेतु निर्धारित परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक से एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा समय समय पर इस क्षेत्र की, की गई मॉनिटरिंग से प्राप्त परिणामों से काफी कम पाया जाना बताया गया है, जबकि सिवियरली पॉलुटेड क्षेत्र होने के कारण यह संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः पूर्व में मॉनिटरिंग किये गये स्थलों पर परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की एक माह की अवधि का गुणवत्ता मापन रिपोर्ट मानसून को छोड़कर अन्य मौसम का (Non Monsoon Season) प्रस्तुत की जाये।

14. उद्योग के द्वारा माह अक्टूबर में 08 स्थलों पर मॉनिटरिंग का कार्य किया गया। इन स्थलों में किये गये मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18.2 से 50.0 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 46.4 से 98.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 6.7 से 13.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.4 से 39.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। इंक्रिमेंटल ग्राउण्ड लेवल कन्संट्रेशन को मॉनिटरिंग परिणामों में समावेश करने पर प्रस्तावित क्षमता विस्तार कार्यकलाप से परिवेशीय वायु में पीएम$_{2.5}$, पीएम$_{10}$, एसओ$_2$ एवं एनओ$_{एक्स}$ की मात्रा में अत्यन्त कम वृद्धि संभावित है।

15. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा माह अक्टूबर 2017 में इस क्षेत्र अर्थात मेसर्स वुलवर्थ (इण्डिया) लिमिटेड, सरोरा, रायपुर में किये गये मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी. एम.$_{10}$ 41.66 से 71.66 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 12.91 से 17.70 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 26.25 से 28.54 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई। इस प्रकार माह अक्टुबर में किये गये मॉनिटनिंग अनुसार एयर क्वालिटी इंण्डेक्स 41.66 (गुड) से 71.66 (सेटिसफेक्ट्री) के मध्य पाया गया।

16. परियोजना के क्षमता विस्तार संबंधी जनसुनवाई के दौरान उपस्थित लोगों द्वारा सराहना करते हुये स्वागत किया गया। स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार प्राथमिकता के तौर पर दिये जाने बाबत् मांग की गई। इस हेतु प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहमति दी गई।

17. एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 221 दिनांक 24/05/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 08/06/2017 को प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार "किसी भी औद्योगिक ईकाई की स्थापना से आसपास का परिवेश प्रभावित होता है एवं इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों

के शमन के लिये प्रभावी उपाय किये जाते है। उद्योग द्वारा मुख्य ईंधन के रूप में प्रोड्यूसर गैस तथा गैसीय फॉयर का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने से उक्त ईकाई की स्थापना से डस्ट पार्टिकल की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।"

18. समिति का मत था कि परियोजना स्थल सिवियरली पॉलुटेड क्षेत्र होने के कारण पार्टिकुलेट मेटर के उत्सर्जन में और नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु पार्टिकुलेट मेटर के उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 40 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर (20 प्रतिशत कठोर) सुनिश्चित किया जाना उचित होगा। साथ ही कच्चे माल / उत्पाद / ठोस अपशिष्टों के परिसर में हेण्डलिंग एवं परिवहन के दौरान फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन में और प्रभावी नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु जल छिड़काव व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाना, आंतरिक सड़कों का पक्काकरण एवं सड़कों / परिसर की नियमित साफ सफाई आदि किया जाना आवश्यक है।

समिति की 241वीं बैठक दिनांक 25/11/2017 में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्लॉट नं 490/1, 237/3, 237/6, 476/1, 476/2, 483, 484, 485, 486, 490/2, 487, 488, 489/2, 474, 489/1, 488, 474, 489/1, 497, 496, 239/1, 239/2, 240, 241, 236/1, 236/2, 327/1, 327/2, 327/3, 328/1, 328/2, 330/1, 330/2, 324/1, 271/5 एवं 271/6, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर में कुल भूमि 7.899 हेक्टेयर में रोलिंग मिल 1,00,000 टन/वर्ष से 2,14,000 टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 77वीं बैठक दिनांक 05/01/2018 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्लॉट नं 490/1, 237/3, 237/6, 476/1, 476/2, 483, 484, 485, 486, 490/2, 487, 488, 489/2, 474, 489/1, 488, 474, 489/1, 497, 496, 239/1, 239/2, 240, 241, 236/1, 236/2, 327/1, 327/2, 327/3, 328/1, 328/2, 330/1, 330/2, 324/1, 271/5 एवं 271/6, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर में कुल भूमि 7.899 हेक्टेयर में रोलिंग मिल 1,00,000 टन/वर्ष से 2,14,000 टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावे।

"वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।"

तदानुसार प्लॉट नं 490/1, 237/3, 237/6, 476/1, 476/2, 483, 484, 485, 486, 490/2, 487, 488, 489/2, 474, 489/1, 488, 474, 489/1, 497, 496, 239/1, 239/2, 240, 241, 236/1, 236/2, 327/1, 327/2, 327/3, 328/1, 328/2, 330/1, 330/2, 324/1, 271/5 एवं 271/6, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर में कुल भूमि 7.899 हेक्टेयर में रोलिंग मिल 1,00,000 टन/वर्ष से 2,14,000 टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. No additional land shall be acquired for expansion project.
2. No furnace oil, LDO, HSD etc. liquid fuel shall be used in the re-heating furnace of rolling mill. Only gas generated from coal gasifier shall be used as fuel in the re-heating furnace of rolling mill.
3. Project authority shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Closed cycle cooling system shall be provided. Minimum water for makeup purposes shall be ensured. Cooling water shall be cooled in cooling system and after cooling reused for cooling purpose. Domestic effluent shall be treated in well-designed septic tank and soak pits. In case of any failure of effluent treatment arrangement, it shall be immediately rectified or same alternate arrangement shall be provided. Treated effluent shall be utilized either in process or for plantation purposes within plant premises. Any liquid effluent what so ever generated from industrial activities and un-treated / treated domestic effluent shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances. The treated domestic effluent shall be used for plantation purpose after proper disinfection. Project authority shall make arrangement of suitable drains / pipe networks to ensure adequate flow for full utilization of treated effluent inside the premises. The concept of zero discharge shall be maintained all the time except during monsoon. Arrangements shall be made that effluents and storm water do not get mixed. Project authority shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Industrial wastewater shall conform to the standards prescribed under GSR 422 (E) dated 19th May, 1993 and December, 1993 or as amended form time to time.
4. Project authority shall provide adequate measuring arrangements for the measurement of water utilized in different categories and effluent generated before commissioning of the plant with expanded capacity.
5. Project authority shall ensure that particulate matter emission shall not exceed 40 mg / Nm^3 under any circumstances by up-gradation / modification of existing air pollution control systems.
6. Project authority shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Scrubber and air recuperator of adequate capacity and high efficiency shall be installed in rolling mill reheating furnace to ensure outlet dust (particulate matter) emission less than 40 mg / Nm^3 all the time. Low NOx burners shall be installed in furnace of rolling mill. Project authority shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate and effective arangement shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant and internal roads shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in rolling mill plant. The emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	40 mg/Nm^3 Forty Milligram per Normal Cubic Meter)

The Chhattisgarh Environment Conservation Board may specify more stringent standards for the relevant parameters keeping in view the nature of the industry and its size and location. At no time the emission level shall go beyond the prescribed standards.

Interlocking facilities shall be provided so that process can be automatically stopped in case emission level exceeds the limit. Project authority shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. Height of the stack attached to reheating furnace of rolling mill shall not be less tahn 44 meters.

7. Secondary fugitive emissions shall be controlled and shall be kept within the prescribed limits and regularly monitored. Guidelines / Code of Practice issued by the CPCB in this regard shall be followed. Project authority shall maintain fugitive dust emissions to the minimum level in the areas of road transportation routs of raw material, product to ensure National Ambient Air Quality Standards prescribed including black topping / asphalting / concreting and maintenance with requisite water sprinkling arrangements.

8. All air pollution control systems shall be kept in good running conditions all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay otherwise similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project authority, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency.

9. Online Continuous Stack Emission Monitoring System shall be installed for measurement of particulate matter. Project authority shall ensure regular transfer of data of Online Continuous Stack Emission Monitoring System to CECB. Regular monitoring of ground level concentration of SO_2, NOx, PM_{10} and $PM_{2.5}$ at at-least four stations shall be carried out in the impact zone and records maintained. The location of the monitoring stations and frequency of monitoring shall be decided in consultation with Chhattisgarh Environment Conservation Board Raipur. The data so collected shall be properly analyzed and periodic reports shall be submitted to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.

10. Project authority shall install separate electric metering arrangements with time totalizer and interlocking arrangement for the running of pollution control devices. These arrangements shall be made in such a fashion that any non-functioning of pollution control device / devices shall immediately stop the electric supply to the fuel / raw materials supply system and shall remain tripped till the pollution control device / devices are made functional again / rectified to achieve the desired efficiency.

11. Project authority shall utilize the fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

12. Project authority shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. End cutting from rolling mill shall be used as raw material in induction furnace units. Mill scales shall be sold to sinter plant / Ferro alloys / Casting units. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Project authority shall obtain authorization from Board for management and handling of hazardous materials as per Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

13. Coal ash from coal gasifier shall be used in fly ash brick plant / land filling and coal tar shall be sold to registered vendors. Mill scales shall be collected through sedimentation pit and utilized as a raw material in steel / ferro alloys plants.

14. All the internal roads shall be made pucca. Regular cleaning of roads shall be ensured. Project authority shall adopt good house keeping practices within premises.

15. Project authority shall take proper action to control the noise pollution. Project authority shall install appropriate noise barriers / control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation to control the noise. Earplugs / ear muffs etc. shall be provided to the employee working in the high noise areas. Leq of / noise levels emanating from machines shall be limited to 75 dBA. The noise level shall not exceed the limits 75 dB (A) during the daytime and 70 dB (A) during the night time within the factory premises. Project authority shall take adequate measures for control of noise level below 85 dB (A) in the work environment. Workers engaged in noisy areas shall be periodically examined to maintain audiometric record and for treatment for any hearing loss including rotating them to non-noisy / less noisy areas.

16. First aid and sanitation arrangements shall be made for the drivers and other contract workers.

17. Up-gradation / modification of effluent treatment system and air pollution control equipments shall be taken up simultaneously with other civil / mechanical works of expansion (if any). The progress of the activities related to the project shall be submitted periodically to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.

18. Adequate safety measures shall be provided in the plant area to check / minimize spontaneous fires. Copy of the these measures with full details along with location plant layout shall be submitted to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.

19. Disaster Management plan shall be prepared to meet any eventuality in case of an accident taking place. Mock drills shall be conducted regularly and based on the same, modifications required, if any shall be incorporated in the DMP.

20. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project authority shall abide by the decisions taken by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Government / Central Pollution Control Board from time to time in this regard. Adequate wide green belt of Local broad leaf species shall be developed in the 1.628 ha land. Central Pollution Control Board guidelines shall be followed in planning and developing green belt and selection of species etc.

21. Plantation shall be completed within first year. Incase project proponent fails to carryout plantation, this environmental clearance may be cancelled.

22. Project authority shall provide garland drains with appropriate check dams all along the raw materials storage areas etc. to avoid any possibility of erosion (wearing away) during rain. Sedimentation pits shall be constructed at the corners of the garland drains. Project authority shall provide adequate collection and treatment arrangement for proper management of storm water. The surface run-off shall be de-silted through a series of check dams and drains.

23. Project authority shall develop rainwater-harvesting structures to harvest the rainwater for utilization in the lean season as well as to recharge the ground water table. A detailed scheme for rainwater harvesting to recharge the ground water aquifer shall be prepared in consultation with Central Ground Water Authority / State Ground Water Board. A copy of the same shall be submitted within three months to the Chhattisgarh Environment

Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.

24. Occupational Health Surveillance of the workers should be done on a regular basis and records maintained as per the factories Act.

25. The project proponent shall also comply with all the environmental protection measures and safe guards recommended in the Environment Impact Assessment Report / Environment Management Plan.

26. Project authority shall establish an environmental management cell to carryout function relating to environmental management under the supervision of senior executive who shall directly report to the head of organization. A full-fledged laboratory with qualified technical / scientific staffs to monitor the influent, effluent, ground water, surface water, soil, stack emission and ambient air quality etc. shall be provided.

27. Adequate funds shall be allocated for undertaking CSR activities (apart from committed plantation) as per Government norms. Project authority must undertake socio-economic development activities in the surrounding villages like community development programmes, educational programmes, drinking water supply and health care etc. Details of activities shall also be submitted to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Naya Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur. The funds earmarked for the environment protection measures shall not be diverted for other purpose and year-wise expenditure should be reported to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Naya Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.

28. The issuance of this environmental clearance does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privileges, nor does not authorize any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or Local laws or regulations.

29. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to revoke the clearance if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to amend / cancel any of the conditions and add new conditions and make further stringent the emission / effluent limit as and when deemed necessary in the interest of environmental protection, change in the project profile or non-satisfactory implementation of the stipulated conditions etc.

30. Local persons shall be given employment during construction (if any) and operation of the plant.

31. The Project authority shall advertise in at least two local newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned within seven days from the date of this clearance letter, informing that the project has been accorded environmental clearance and copies of clearance letter are available with the Chhattisgarh Environment Conservation Board and may also seen at Website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change at www.envfor.nic.in and website of SEIAA, Chhattisgarh at www.seiaacg.org.

32. Half yearly report on the status of implementation of the stipulated conditions and environment safeguards shall be submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.

33. Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change at Nagpur shall monitor the implementation of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report and Environment Management Plan along with the additional information submitted from time to time shall be forwarded to the Regional Office for their use during monitoring.

34. The project authorities shall inform the Regional Office as well as the SEIAA, Chhattisgarh regarding the date of start of commissioning of plant with expanded capacity.

35. Full cooperation shall be extended to the Scientists / Officers from the SEIAA, Chhattisgarh, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Bhopal / the CPCB / the Chhattisgarh Environment Conservation Board, who would be monitoring the compliance of environment status.

36. Concealing factual data or submission of false / fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

37. In case of any deviation or alteration in the expansion project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / SEIAA, Chhattisgarh.

38. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

39. The above stipulations would be enforced among others under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) act, 1986 and rules there under, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and its amendments, the Public Liability Insurance Act, 1991 and its amendments.

40. The above conditions would be enforced inter-alia, under the provisions of the water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act. 1981 the environment (Protection) Act. 1986 and the public liability insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules. The proponent shall ensure to provide for the costs incurred for taking up remedial measures in case of soil contamination, contamination of groundwater and surface water, and occupational and other diseases due to the mining operations.

41. Chhattisgarh Environment Conservation Board shall display a copy of the clearance letter at the Regional Office, District Trade and Industries Centre and Collector's Office / Tehsildar's Office for 30 days.

Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010

सदस्य सचिव
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़

पृ. क्र. /एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./एसआईए/सीजी/आईएनडी /468 नया रायपुर, दिनांक / /2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492001
2. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 100003
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भूतल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) 440001
4. कलेक्टर, जिला–रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
छत्तीसगढ